राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 23.08.2013 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की जून 2013 की समीक्षा बैठक दिनांक 23.08.2013 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री माजिद अली, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री संजीव मित्तल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (नियोजन); श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस, आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आई.ए.एस, खाद्य आयुक्त; श्री सौरभ बाबू, आई.ए.एस, निदेशक पंचायती राज; श्री एल. वेंकटेश्वरलू, आई.ए.एस, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त; डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम., उ.प्र. शासन; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रुप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री माजिद अली, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री संजीव मित्तल, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (नियोजन); श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस, आयुक्त (ग्राम्य विकास); श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आई.ए.एस, खाद्य आयुक्त; श्री सौरभ बाबू, आई.ए.एस, निदेशक पंचायती राज; श्री एल. वेंकटेश्वरलू, आई.ए.एस, सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त; डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम.; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये कहा कि सदन में आप सभी की उपस्थिति निश्चय ही इस बात का परिचायक है कि हम सभी अपने प्रदेश तथा इसकी जनता के उत्थान के प्रति जागरुक है। श्री गर्ग ने निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- माननीय डा0 डी. सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित 15.01.2013 की विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे, के अन्तर्गत अभी तक की प्रगति सन्तोषजनक है। दिनांक 17.08.2013

को माननीय मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन श्री जावेद उस्मानी ने इस विषय पर व्यापक समीक्षा की और बताया कि 01.01.2013 से 31.07.2013 तक कुल -765- नयी शाखायें खोली गयी हैं जो सितम्बर त्रैमास तक के लक्ष्य -1350- का लगभग 57% है। उन्होने -3000- शाखाओं के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति मार्च 2014 तक करने का **आह्वाह्न** किया तथा बैंको एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों की अपेक्षा की।

- बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने स्थापना दिवस 20.07.2013 को एक ही दिन में -106- नयी शाखायें खोलकर प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी शाखाओ में ए.टी.एम. भी स्थापित कर दिये गये है।
- उन्होने यह भी बताया कि विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में चयनित -12- जनपदों में से केवल एक जनपद को छोड़कर अन्य सभी जनपदों मे ऋण जमा अनुपात में व्यापक वृद्धि हुई है जो सराहनीय है। श्री गर्ग ने बैंको द्वारा वित्त पोषित किये जाने वाली यूनिटस में राज्य सरकार से सहयोग न मिल पाने के कारण महसूस की जा रही समस्याओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया।
- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद भी शामिल है। दिनांक 13.06.2013 एवं 30.07.2013 को लखनऊ व दिल्ली में आयोजित बैठकों में हमारे प्रदेश की प्रगति की सराहना की गयी है साथ ही साथ हमारी कुछ कमियों को भी इंगित किया गया है यथा Non seeding of Aadhaar number with the beneficiaries accounts, Non issuance of Debit Cards to all Beneficiaries and non installation of ATMs in all Branches.

  उन्होने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा Remote Aadhaar Seeding Framework (RASF) की सुविधा भी प्रारम्भ की है जिसके द्वारा आधार नम्बर की सीडिंग की जा सकती है।
- प्रदेश में ऐसे छोटे काश्तकार तथा कृषक जिनका बकाया ऋण लगभग ₹ 1.00 लाख है, को ब्लाक स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित कर ऋण अदायगी व पुन: ऋण सुविधा हेतु कृषि एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रेरित किया जाना चाहिये ताकि जिससे इन काश्तकारो को रुपे कार्ड की सुविधा प्रदान की जा सके।
- बुनकर समुदाय हेतु भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुये श्री गर्ग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान -70000- कार्डो को जारी करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु सभी बैंको द्वारा सहयोग की अपेक्षा की। नोडल एजेन्सी द्वारा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु विभिन्न जनपदों में विशेष क्रेडिट कैम्पस आयोजित करने का जो कार्यक्रम तैयार किया गया है उसमें भी पूर्ण सहभागिता का अनुरोध किया।
- भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार नयी शाखाओं के उद्घाटन आदि कार्यक्रमों मे स्थानीय माननीय सांसद को आमंत्रित करने हेतु सभी बैंको द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गयी।
- श्री गर्ग ने निरंतर अनुरोध एवं अनुश्रवण के बावजूद ऑन-लाइन एस.एल.बी.सी. डाटा प्रेषण में पायी जा रही कमियों तथा एस.एल.बी.सी. द्वारा वास्तविक प्रगति

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० ZONAL OFF. U.P. & U. ZONE, LKO.

प्रस्तुत न कर पाने पर खेद व्यक्त करते हुये सभी बैंको द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देने का अनुरोध किया।

स्वागत सम्बोधन के अंत में श्री गर्ग ने सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखो, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग व मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये पुनः इस बैठक में स्वागत किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये कहा कि राज्य स्तरीय बैकर्स समिति का मूल उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं व राज्य सरकार के मध्य एक सेतु की भूमिका निभाते हुये विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करना है। उन्होने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- डी.बी.टी. योजना के अंतर्गत राज्य सरकार व बैंको द्वारा संयुक्त रुप से आवशयक कार्यवाही अनिवार्य है ताकि दूसरे चरण में प्रदेश में चयनित -6- जनपदों में यह कार्य सुचारु रुप से किया जा सके. एसएलबीसी द्वारा आवश्यक अनुश्रवण करते हुये विभिन्न आवश्यक औपचारिकताओं यथा जिलाधिकारी से लाभार्थियों की योजनावार डिजिटाइज सूची प्राप्त करना, बैंक खाते से आधार संख्या की सीडिंग, बैंकिंग संरचना के सुदृढ़ीकरण आदि की कार्यवाही की गयी है जो सराहनीय है। विभिन्न स्तरों पर sensitization की विशेष आवश्यकता है। उन्होने डी.बी.टी. व डी.बी.टी.एल. योजनाओं से सम्बन्धित सभी मानकों की समयबद्ध रुप से पूर्ति हेतु अनुरोध किया।
- स्वाभिमान योजना के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों मे बैकिग सेवाओ के विस्तार का कार्य बैंको द्वारा मार्च 2012 तक सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया गया है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -76855- गावों मे बैकिग सेवाओ के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार किया गया है जिसकी अभी तक की प्रगति असंतोषजनक रही है जिसके लिये एक कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन का अनुरोध किया। उन्होने प्रत्येक शाखा में ए.टी.एम. की स्थापना, सभी पात्र किसानों को रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करना आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर नवीन निर्देशों की जानकारी दी तथा आह्वाहन किया कि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को लागू करें ताकि बैंक अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ लाभ भी हासिल कर सके।
- वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रथम त्रैमास में दर्ज 20.09% प्रगति का जिक्र करते हुये श्री श्रीनिवास ने कहा कि यद्यपि यह उपलब्धि गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कुल ऋण वितरण व प्रतिशत उपलब्धि मानकों में अधिक रही है तथापि आवश्यकता इस बात की हैं इसमें आशातीत सुधार किया जाये।
- प्रदेश मे अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त वित्तीय सुविधाओ की प्रगति पर हर्ष व्यक्त करते हुये उन्होने अधिक से अधिक ऋण प्रवाह हेतु अनुरोध किया।
- प्रदेश में बैक ऋण वसूली की स्थिति का जिक्र करते हुये उन्होने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया।

- अन्य महत्वपूर्ण विषयों यथा - आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि आवंटन तथा जिन आरसेटीयों को भूमि आवंटित हो चुकी है उन स्थानो पर लीजडीड निष्पादित करते हुये भूमि पर भौतिक कब्जा करने के उपरांत भवन निर्माण की प्रक्रिया यथा शीघ्र प्रारम्भ की जाये, शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यो की शत प्रतिशत पूर्ति, बुनकरो हेतु भारत सरकार की विशेष राहत योजना का क्रियांवयन जिसके अंतर्गत बुनकर क्रेडिट कार्ड के लक्ष्यो की शत प्रतिशत पूर्ति इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हुये श्री श्रीनिवास ने सभी स्टेक होल्डर्स को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु आमंत्रित किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में विद्यमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

श्री माजिद अली, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ. प्र. शासन ने कहा कि राज्य सरकार व बैंकर्स को आपस में समंवय स्थापित कर प्रदेश के विकास पर बल देना चाहिये। उन्होने प्रदेश में बैको द्वारा ऋण जमा अनुपात में दर्ज व्यापक वृद्धि पर संतोष व्यक्त करते हुये आह्वाह्न किया ऐसे -22- जनपद जिनमें ऋण जमा अनुपात अभी भी 30% से कम है में व्यापक सुधार हेतु बैंकर्स द्वारा विशेष प्रयास किये जाये। उन्होने विभिन्न विकास कार्यक्रमों वित्तीय समावेशन कार्यक्रम व वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति क्रियान्वयन व सफलता हेतु सकारात्मक प्रयास किये जाने पर बल दिया। उन्होने ऋण वसूली व कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विषयो पर प्रदेश सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से पधारे डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.) ने निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत वर्तमान में -20- जनपदो में एल.पी.जी. स्कीम लागू है तथा 01.09.2013 से यह योजना अन्य -35- जनपदो में भी लागू हो जायेगी।
- उन्होने यह भी बताया कि वर्तमान में इन चयनित -20- जनपदों में 50% आधार कार्डस की सीडिंग हो चुकी है तथा 31.08.2013 तक इसे 70% करने आह्वाह्न किया। श्री पाण्डे ने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में अग्रणी जिला प्रबन्धकों को जनपद में कार्यरत सभी बैंको द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाये ताकि योजना का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा सके।

  इसी क्रम में सभी बैंको द्वारा प्रदेश स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किये जाने हेतु डा0 पाण्डे ने निर्देशित किया। उन्होने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गत 26 जुलाई 2013 कि जारी निर्देशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जिसके माध्यम से यह अपेक्षा की गयी है कि डी.बी.टी. योजना के सफल क्रियान्वयन व संचालन हेतु बैंकर्स द्वारा अपने ग्राहकों से भी सम्पर्क किया जाये।
- आरसेटीज संसथानों की स्थापना हेतु प्रदेश शासन द्वारा नि:शुल्क भूमि आवंटन के साथ साथ बैंको द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता, रोजगार सृजन, संकाय

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ० प्र० U.P.G.U. ZONAL OFFICE

सदस्यो की उपलब्धता आदि पर वि
उच्च स्तर की रहे।

- शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत वित्त
शतप्रतिशत पूर्ति हेतु सघन प्रयास एवं
देना आवश्यक है। उन्होनें कहा कि आ
मांग अधिक होती है अतः बैकों द्वारा स
- सभी किसान क्रेडिट कार्डस को ए.टी.
माध्यम से किसानो को सुविधा प्रद
उपयोग किया जा सके।

अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को ऋ
की ओर इंगित करते हुये श्री पाण्डे ने
हेतु निर्देशित किया। प्रसंगवश, मान
कार्यक्रमानुसार बैकों द्वारा अपने प्राथमि
प्रवाह अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों व

श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रि
बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवा

- दिनांक 15.01.2013 को डा0 डी सुब्बार
अध्यक्षता मे सम्पन्न विशेष एस.एल.ब
नयी शाखाओं की स्थापना हेतु जो
कार्यक्रमानुसार क्रियांवयन सुनिश्चित वि
वे ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक f
अधिक ग्रामीणों को बैंक से जोड़ा जा स
- लीड बैक योजनांतर्गत राज्य स्तरीय बैं
एस.- IV प्रारुप में अगले तीन वर्षों के
कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किय
- डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत उन्होंने
गावों को कवर करके नये खाते व f
आह्वाह्न किया।
- एस.एल.बी.सी. द्वारा प्रेषित किये जाने
हेतु आवश्यक है कि सभी बैक निर्धा
एस.एल.बी.सी. को करें ताकि एस.एल
रिजर्व बैंक को प्रेषित कर सके। बैंक
अधिकारी को नोडल अधिकारी चयनित
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के सफल f
कनेक्टिविटी एवं अन्य बुनियादी सुविध

राज्य सरकार व बी.एस.एन.एल. के संयुक्त प्रयासों द्वारा समस्या का समाधान सम्भव है।

- करेंसी मैनेजमेंट से सम्बन्धित बिन्दुओं पर बैको के स्तर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नियमों व दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- राज्य सरकार द्वारा बैको को सभी सम्भव सहयोग प्रदान किया जाये ताकि बैंकर्स निर्धारित कार्य को सुगमता से क्रियांवयित कर सके।
- श्री पसरीचा ने बताया कि कई स्थानो पर बी.सी. सर्वर को सी.बी.एस. सर्वर के साथ एकीकृत नहीं किया गया है जिसके कारण आई.सी.टी. आधारित बी.सी. मॉडल ग्रामीणो एवं बैको को वांछित परिणाम नहीं दे पा रहा है।
- उन्होने डी.सी.सी. व डी.एल.आर.सी. की बैठकों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जनपद स्तर पर इन महत्वपूर्ण बैठकों का समयबद्ध आयोजन सम्पन्न किया जा सके।
- उन्होने एस.एल.बी.सी. फोरम को मार्ग-दर्शन एवं दिशा-निर्देशन हेतु प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति हेतु भी इंगित किया।

श्री के. के, गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- राज्य में कृषि ऋण प्रवाह में व्यापक वृद्धि हुई है। प्रदेश में ऐसे छोटे और सीमांत किसान जो औसत 2 एकड़ जमीन की श्रेणी में आते है, ने कृषि के क्षेत्र में लगभग 90% की प्रगति कर अन्य किसानो को प्रोत्साहित किया है।
- हमें प्रदेश एवं इस किसान समुदाय के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जिसके लिये एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है क्योंकि यह वो क्षेत्र है जहाँ व्यापार के उचित अवसर अधिक नही है, पर्याप्त आय नहीं है और जहां बिक्री योग्य सरप्लस पर्याप्त नहीं है। उन्होने इसके लिये निम्न सुझाव दिये:-
  - किसानो को समूहों मे एकत्र करने हेतु प्रेरित करना जैसे कि संयुक्त देयता समूहों, स्वयं सहायता समूहो आदि का गठन,
  - संसाधनों का एकीकरण तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु समन्वय,
  - उत्पादक समूहों का एकत्रीकरण जिससे छोटी छोटी बचत को बड़ी बचत मे परिवर्तित किया जा सके,
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 31.08.2013 तक सभी किसान क्रेडिट कार्डस को ए.टी.एम. सक्षम बनाया जाने का लक्ष्य दिया था ताकि रुपे कार्ड के माध्यम से किसानो को सुविधा प्रदान की जा सके।
- कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं यथा फसली ऋण के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता; सुअर पालन, बागवानी व दुग्ध विकास के लिए अल्पावधि ऋण/ आर्थिक सहायता के अंतर्गत कवर करना

- राज्य सरकार भी कृषि ऋण को बढ़ावा देने के लिए कृषि नीति की समीक्षा करें और औद्योगिक ऋण नीति के समान ही Single Window Approach को बढ़ावा दे।
- राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कामधेनु योजना, मुर्गी पालन के लिए 30000 पक्षी परियोजना पर हर्ष व्यक्त करते हुये उन्होने कहा कि इन परियोजनाओं के विस्तार से जहाँ एक ओर किसानों की आय मे वृद्धि दर्ज होगी वही दूसरी ओर छोटे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण भंडारण योजना के अंतर्गत प्रदेश में केवल -348- ग्रामीण गोदामों को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त है जोकि अन्य राज्यों की तुलना काफी कम है।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 1:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 23.05.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

विगत बैठक दिनांक 23.05.2013 का कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 18.06.2013 प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या 2:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 23.05.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट</u>

(I) <u>प्रदेश के सभी जनपदो में बैको द्वारा आरसेटी की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन</u>

चर्चा के दौरान सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा मात्र -18- जनपदों में ही नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -47- अन्य जनपदों में आवंटन प्रस्ताव शासन के विचार एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है तथा यह प्रकिया सितम्बर 2013 के प्रथम सप्ताहांत तक पूरी हो जायेगी।

विस्तृत चर्चा के दौरान श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस., आयुक्त (ग्राम्य विकास), उ.प्र. शासन ने कहा कि :-

- भूमि आवंटन इत्यादि से सम्बन्धित मामलों को जनपद स्तरीय डी.सी.सी./डी.एल.आर.सी. बैठकों मे उठाना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर समाधान सम्भव हो सके।
- -47- अन्य जनपदों में प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटन की प्रक्रिया सितम्बर 2013 के प्रथम सप्ताहांत तक पूरी हो जायेगी। जहाँ आरसेटीयों को भूमि आवंटित हो चुकी है उन स्थानो पर लीजडीड निष्पादित करते हुये भूमि पर भौतिक कब्जा करने के उपरांत भवन निर्माण की प्रक्रिया यथा शीघ्र प्रारम्भ की जाये।

* उन्होने सदन को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये आरसेटी के लक्ष्यों से अवगत कराते हुये बताया कि प्रत्येक जनपद में -750- प्रशिक्षणार्थियों को इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रशिक्षित करना है। इसी क्रम में उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि वे अपने अग्रणी जिला प्रबन्धको के माध्यम से इस कार्य को सम्पादित करें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हो सके।

उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुये श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि प्रदेश में आरसेटीज की व्यापक समीक्षा हेतु एक उप समिति का गठन अनिवार्य है। इसके लिये उन्होने यह प्रस्ताव रखा कि महाप्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया जाये जिसमे आरसेटी के स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को भी सदस्य के रुप में सम्मिलित किया जाये। इस उप समिति की पहली बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाये ताकि आरसेटी से सम्बन्धित सभी पहलूओं पर विस्तृत चर्चा की जा सके।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने कहा कि उप समिति की एक विशेष बैठक शीघ्र आयोजित कर इन मुद्दों का समाधान किया जाये।

(II) <u>सभी पात्र परन्तु वंचित किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाना एवं आंकड़ो का मिलान</u>

सदन को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही में कुल 13.07 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है जिसमें से नवीनीकरण की कार्यवाही 9.60 लाख मामलों में व नये कार्ड जारी करने की कार्यवाही 3.46 मामलों में की गयी है। साथ ही प्रदेश के -13- जनपदों को संतृप्त घोषित किया जा चुका है तथा सभी पात्र मामलों में रुपे कार्ड 31.08.2013 तक जारी करने की कार्यवाही बैंको द्वारा शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस. आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने अपेक्षा की कि सम्बन्धित विभाग किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जनपदवार प्रगति एस.एल.बी.सी. बैठकों में प्रस्तुत करें तथा जनपद स्तरीय डी.सी.सी. /डी.एल.आर.सी. बैठकों में इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिये।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने बताया कि निरन्तर अनुरोध के बावजूद कृषि निदेशालय, उ.प्र. द्वारा जनपदवार प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नही करायी जा रही है। बैंको से प्राप्त फीडबैक के अनुसार जनपदों में योजनांतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या लगभग नगण्य है जबकि कृषि विभाग द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लम्बित होने से अवगत कराया जाता है।

श्री वी. के. सिंह, निदेशक (कृषि सांख्यकि) ने शीघ्र ही लम्बित आवेदन पत्रों की सूची उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

(III) <u>3000 नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर पर 3 प्रतिशत प्वाइंटस की वृद्धि</u>

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार विगत 29.03.2013 को लखनऊ में आयोजित -300- नयी शाखाओ के उद्घाटन समारोह व चयनित जनपदों में ऋण जमा अनुपात में निरंतर दर्ज की जा रही वृद्धि का उल्लेख करते हुये विश्वास व्यक्त किया गया कि बैको, राज्य सरकार एवं सभी स्टेक होल्डर्स के संयुक्त प्रयासों से सभी लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेगें।

(IV) <u>राज्य के -6- चयनित जनपदो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) स्कीम का क्रियान्वयन</u>

डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद भी शामिल है। दिनांक 13.06.2013 एवं 30.07.2013 को लखनऊ व दिल्ली में आयोजित बैठकों में हमारे प्रदेश की प्रगति की सराहना की गयी है साथ ही साथ हमारी कुछ कमियों को भी इंगित किया गया है यथा Non seeding of Aadhaar number with the beneficiaries accounts, Non issuance of Debit Cards to all Beneficiaries and non installation of ATMs in all Branches.

इन सभी मानकों में बैंकों व नोडल विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया।

(V) <u>बैंक देयों की वसूली</u>

चर्चा के दौरान श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सदन को हाल ही में बुन्देलखण्ड मामले में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अवगत कराया।

कार्यसूची संख्या 3:- <u>वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत प्रगति</u>

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित -6- जनपदों यथा इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बडौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी.

जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गयी। इस समीक्षा में निम्न बिन्दु उभरकर सामने आये :-

- विभिन्न योजनाओं की लाभ्यार्थीवार सूची सम्बन्धित विभाग द्वारा अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध कराने में समस्या आ रही है।
- जनपदो में प्रीमेट्रिक स्कॉलरशिप योजनान्तर्गत केवल कक्षा 9 व 10 के छात्रों को ही शामिल किया जाना है।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो गये है, लाभ्यार्थियों के खाते खुल गये है तथा उन्हें डेबिट कार्ड भी जारी कर दिये गये है परन्तु अभी तक अधिकांश खातों में आधार कार्डस की सीडिंग नहीं हो रही है। इस क्रम में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने अवगत कराया कि नोडल विभाग द्वारा आधार नम्बर की सूची न मिलने के कारण खातों में आधार कार्डस की सीडिंग नहीं हो पा रही है तथा आश्वस्त किया कि सूची मिलने के उपरांत आधार सीडिंग की प्रक्रिया बैको द्वारा पूरी कर ली जायेगी। उन्होने आधार एनरोलमेंट को गति प्रदान करने पर भी बल दिया।

कार्यसूची संख्या 4:- <u>हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन</u>

योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु योजनांतर्गत -70000- कार्डस जारी करने का संशोधित लक्ष्य तय किया गया है जिसका वितरण सभी बैको को किया जा चुका है। इसी क्रम में नोडल ऐजेंसी द्वारा कुछ क्लस्टर भी चयनित किये गये है जिनमें विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम तय कर सभी सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी बैको से योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण एवं लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति हेतु कैम्प लगाने का अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 5:- <u>वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रगति समीक्षा</u>

वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत जून 2013 तक बैंको द्वारा दर्ज की गयी कुल प्रगति 20.09% रही है जो विगत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (16.17%) की तुलना में अधिक रही है। सेक्टरवार कृषि, लघु उद्यम एवं सेवाओ के अंतर्गत दर्ज प्रगति क्रमशः 19.28%, 28.88% व 15.93% रही है।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रगति में सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके योगदान से प्रदेश का कुल उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाया जा सके। सदन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अच्छे मानसून की सम्भावनाओं के दृष्टिगत शतप्रतिशत लक्ष्य पूर्ति हेतु समग्र प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त, उ.प्र. शासन ने कहा कि कुछ ऐसे बैंक जिनकी उपलब्धि प्रदेश स्तरीय औसत प्रगति से कम रही है, से इसके कारण जानने चाहे तथा उन्हें आगामी तिमाही में वार्षिक ऋण योजना में सुधार का अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 6:- <u>ऋण जमा अनुपात</u>

ऋण जमा अनुपात के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का जून 2013 तक का ऋण जमा अनुपात विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष क्रमशः 7.29% व ऋण : निवेश + जमा अनुपात 7.40% बढ़ा है।

चर्चा के दौरान श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशो के अनुसार डाटा रिपोर्टिंग का अनुरोध दोहराया जिसके अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत ऐसी इकाईयां जिनका ऋण स्वीकृत एवं वितरण किसी दूसरे प्रदेश के बैंको द्वारा किया गया है का विवरण अपने प्रदेश की उपलब्धि में सम्मिलित किया जाना चाहिये तथा इसका उचित वर्गीकरण किया जाये।

श्री गर्ग ने बताया कि प्रदेश मे ऋण जमा अनुपात की विस्तृत समीक्षा हेतु एक उप-समिति का गठन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में किया गया है।

कार्यसूची संख्या 7:- <u>प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा</u>

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समंवयन में एक उप-समिति गठित है जिसकी नियमित बैठकों में योजना की प्रगति समीक्षा की जा रही है। उप-समिति की अभी तक -5- बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

इसी क्रम में अवगत कराया गया कि 29.07.2013 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नयी दिल्ली में राज्य स्तरीय बैकर्स समिति संयोजकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी जिसमें हमारे प्रदेश की प्रगति पर भी चर्चा की गयी। बैठक में लिये गये निर्णयों एवं विभिन्न कार्यबिन्दुओं से समिति के सभी सदस्यों को राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) के द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

कार्यसूची संख्या 8:- <u>किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सभी पात्र परंतु वंचित किसानों को आच्छादित किया जाना</u>

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने कृषि विभाग द्वारा जनपदवार/बैंकवार लम्बित ऋण आवेदन पत्र की सूचना प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया ताकि आकडों का मिलान एवं सही प्रगति रिपोर्ट प्रेषित की जा सके।

श्री वी. के. सिंह, निदेशक (कृषि सांख्यकि) ने फसल बीमा की योजनाओ की जनकारी देते हुये सदन को अवगत कराया कि :-

- ♣ खरीफ 2013 में -4- जनपदो यथा बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर तथा अमरोहा में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY) चालू है।
- ♣ इस योजना के अन्तर्गत सभी ऋणी कृषको का आच्छादन अनिवार्य है तथा गैर ऋणी कृषको के लिये आच्छादन ऐच्छिक है।
- ♣ मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रदेश के -10- जनपदों यथा मथुरा, मैनपुरी, शाहजहॉनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, रायबरेली एवं फैजाबाद में पायलेट आधार पर पहली बार लागू की गयी है। पूर्व में यह केवल -5- जनपदों में की गयी थी।
- ♣ राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत -71- जनपदों को कवर किया गया है।
- ♣ जिन जनपदो में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गयी है वहॉ ऋणी कृषको का आच्छादन इसी योजनांतर्गत अनिवार्य है। गैर ऋणी कृषक मौसम आधारित फसल बीमा योजना अथवा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मे से अपनी इच्छानुसार किसी भी योजना में भागीदारी कर सकते है।
- ♣ रबी 2013 के लिये भी इसी प्रकार बीमा योजना लागू की जायेगी।

उन्होने बैंको से अनुरोध किया कि बीमा कम्पनियों द्वारा वितरित क्लेम की राशि को यथा शीघ्र 7 दिनो के अन्दर लाभ्यार्थियो के खाते में प्रेषित किया जाये।

कार्यसूची संख्या 9:- <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम</u>

प्रदेश मे कार्यरत बैंको की जून 2013 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री सर्वेश्वर शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर, उद्योग निदेशालय, कानपुर ने सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजनान्तर्गत प्रगति की समीक्षा के लिये एस.एल.बी.सी. द्वारा तैयार प्रारुप पर नियमित रुप से बैंको द्वारा डाटा प्रेषण पर बल देते हुये एस.एल.बी.सी. से अनुरोध किया कि इसकी प्रगति भी एस.एल.बी.सी. की बैठक में प्रस्तुत कर चर्चा की जाये।

श्री डी. के. गर्ग ने सी.जी.टी.एम.एस.ई. योजनान्तर्गत बैंको को सभी पात्र मामलों में कवरेज प्रदान करने का आह्वाहन किया तथा यह भी आश्वासन दिया कि अगली प्रगति समीक्षा में उक्त प्रारुप पर बैंको से प्राप्त डाटा को सदन के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाये।

डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ससमय दावे का निपटारण करने पर बल दिया एवं अवगत कराया कि बैंको के लिये यह चिंता का कारण है, तथा सिडबी से आये हुये प्रतिनिधि से अनुरोध किया कि लम्बित दावों के निस्तारण को यथोचित गति प्रदान की जाये।

कार्यसूची संख्या 10:- <u>साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह</u>

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अंतर्गत आद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दियागया कि इस योजना में सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिये ताकि गरीब एवं कमजोर वर्ग को साहुकारों से मुक्ति दिलायी जा सके।

कार्यसूची संख्या 11:- <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत व गैर निष्पादक आस्तियो के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति</u>

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना सदन द्वारा की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया।

श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय ने बैंको से अपेक्षा की कि विभिन्न जनपदो में वसूली में आ रही परेशानियों की जनपदवार सूची तैयार कर संस्थागत वित्त निदेशालय को प्रेषित की जाये ताकि माननीय मुख्य सचिव महोदय के हस्तकक्षेप से इन मामलो का निपटारण अतिशीघ्र किया जा सके। इसी क्रम में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक एस.एल.बी.सी. ने प्रदेश में कार्यरत सभी अग्रणी बैंको से अनुरोध किया कि अपने सम्बन्धित अग्रणी जनपदों की सूची तैयार कर संस्थागत वित्त निदेशालय को प्रेषित करें जिससे वसूली की स्थिति में व्यापक सुधार आ सके।

कार्यसूची संख्या 12:- <u>अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता</u>

प्रदेश में कार्यरत बैकों की जून 2013 तक की प्रगति समीक्षा प्रस्तुत की गयी। साथ ही चयनित -21- जनपदों की विस्तृत सूचना प्रेषण हेतु बैंको से अनुरोध किया गया।

डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम.एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार नें बैंको से विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों मे ऋण प्रवाह को बढाने पर जोर डालते हुये यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशो के अनुसार ऐसे ऋण, जो "लिमिटेड कम्पनियो" जिनके प्रोमोटर अल्पसंख्यक समुदाय के है, को दिये गये है वह अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण के रुप में शामिल नहीं किये जायेगे यदि पार्टनरशिप कम्पनी को ऋण दिया गया है और पार्टनर अल्पसंख्यक समुदाय के है तो वह ऋण स्वतः ही इस योजना की परिधि में आ जायेगें। उन्होने बैंको से सही डाटा रिपोर्टिंग के लिये भी अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 13:- <u>स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)</u>

प्रदेश में कार्यरत सभी बैकों की आलोच्य अवधि एवं योजना के प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

सदन ने चर्चा के दौरान एस.एल.बी.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम्य विकास विभाग तथा नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के क्रम में सभी स्वयं सहायता समूहों का डाटा बेस तैयार करने हेतु एक फार्मेट तैयार कर बैकों को प्रेषित किया जा चुका है। इस क्रम मे सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कर दें तथा दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार प्रेषण सुनिश्चित करें।

कार्यसूची संख्या 14:- <u>विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोज़गारपरक कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा</u>

(क) <u>स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY):</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी जिसके अंतर्गत समूहों व व्यक्तिगत स्वरोज़गारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने से अवगत कराया गया।

चर्चा के दौरान श्री के. रवीन्द्र नाईक, आई.ए.एस. आयुक्त (ग्राम्य विकास) ने सदन को अवगत कराया कि इस वित्तीय वर्ष से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना एन.आर.एल.एम. योजना में परिवर्तित की जा चुकी है। उन्होने इस नवीन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इस योजना की विस्तृत जानकारी ग्रामीण क्षेत्रो की बैंक शाखाओ तक प्रसारित करने की अनिवार्यता पर बल डालते हुये विभिन्न कार्यशालाओं के आयोजन करने का अनुरोध किया।

(ख) <u>स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी।

(ग) <u>प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम तिमाही की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान श्री वी. पी. गुप्ता, सहायक निदेशक, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने सदन को अवगत कराया कि योजनांतर्गत इस वर्ष 187 करोड़ का बजट निर्धारित किया जा चुका है तथा जनपदवार लक्ष्य एस.एल.बी.सी. के माध्यम से वितरित किये जा चुके है। साथ ही उन्होने सदन को इस योजना के निर्धातित समय सीमाओ से अवगत कराते हुये सभी बैंको से इसका पालन करने का अनुरोध किया।

(घ) <u>सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):</u>

इस योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी तथा बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की गयी।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन ने सभी बैंको से अनुरोध किया कि यह दुधारु पशुओं के लिये अनुकूल समय है तथा सभी बैंको को इसका लाभ उठाते हुये सभी लम्बित मामलों में शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा "कामधेनु" योजना लागू की जा रही है।

(च) <u>विशेष समन्वित योजना</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। समीक्षा के दौरान श्री पी. सी. सिंह, महाप्रबंधक, उ. प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने अवगत कराया कि बैंकों में काफी संख्या में ऋण आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं जिनका शीघ्र निस्तारण बैंकों के सहयोग से किया जाना अपेक्षित है।

श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) ने अवगत कराया कि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त बैंकवार मासिक प्रगति रिपोर्ट सभी बैंकों को हमारे मध्यम से प्रेषित की जाती है ताकि बैंकों के स्तर से वांछित कार्यवाही यथाशीघ्र सम्भव हो सके। उन्होंने इस प्रकरण पर LDMs की समीक्षा बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा का आश्वासन भी दिया एवं उसमें विभाग की उपस्थिति हेतु अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 15:- <u>भारत सरकार की नवीन योजनायें</u>

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित नवीन योजनाओं तथा एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिज़नेस केन्द्र, ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचलित योजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 16:- <u>शिक्षा ऋण</u>

एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा की शुरूआत करते हुए डा0 आलोक पाण्डे, निदेशक (सी.पी. व एम. एफ.), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु शिक्षा ऋण योजना के लक्ष्यों का प्रदेशवार आवंटन किया जा चुका है और बैंकों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति अपेक्षित है। डा0 पाण्डे ने "वर्तमान" को शिक्षा ऋण प्रवाह के लिये अनुकूल समय बताते हुये सभी बैंको से लाभार्थियों को ऋण सुविधायें प्रदान करने पुन: अनुरोध किया। उन्होंने शिक्षा ऋण योजना के बेहतर प्रचार-प्रसार व मार्केटिंग की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. शासन ने इसी क्रम में कहा कि यदि सम्भव हो तो बैंकों द्वारा एक वृहद ऋण शिविर का आयोजन किया जा सकता है।

कार्यसूची संख्या 17:- <u>बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले</u>

सदन को अवगत कराया गया कि इस त्रैमास में केवल एक घटना घटित हुई जो सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी है :-

"महाप्रबन्धक, सर्व यू.पी.ग्रामीण बैंक, मेरठ ने पत्रांक यो.एवं.वि./एस.एल.बी.सी./503 दिनांक 12.06.2013 द्वारा अवगत कराया है कि किन्ही अराजक/शरारती तत्वों द्वारा समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाईम्स (श्रावस्ती- बलरामपुर संसकरण) दिनांक 06.06.2013 में फ्राड करने/अवैध रूप से आर्थिक फायदा उठाने के उद्देश्य से बैंक की जनपद बलरामपुर की समस्त शाखाओं में बैंक खाते खोलने हेतु एजेंटों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर बी.सी.ए. की निर्धारित वेतन पर नियुक्ति का भ्रामक विज्ञापन दिया गया है।"

यह एक गंभीर मामला है तथा इस मामले में संबंधित बैंक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज़ करा दी गयी है। मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता के मद्देनज़र इसे सदन के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया।

कार्यसूची संख्या 18:- <u>अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से</u>

निम्न -3- बिन्दु सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये:-

1. श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार उन ऋणों का विवरण जो कि ऋण उपयोग के स्थान के अनुसार प्रदेश के ऋण जमा अनुपात की गणना मे शामिल किये जाये तथा विफल एटीएम लेनदेन का विवरण.
2. कारीगरों और पट्टेदार किसानों को ऋण देने से संबंधित समस्यायें एवं डाटा बेस का विवरण.

सदन में चर्चा के दौरान श्रीमती अर्चना अग्रवाल, आई.ए.एस, खाद्य आयुक्त ने भारत सरकार की नवीन योजना "National Mission for Technology for Mordanisation of Food Processing Units" की मुख्य विशेषताओ को वर्णित किया। यह योजना उद्यान विभाग के अंतर्गत क्रियान्वयित की गयी है। उन्होने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत 50 लाख की सब्सिडी एवं ब्याज सब्सिडी के रुप में 7% ब्याज का प्रावधान है। उन्होने बैंको से आह्वाहन किया कि वे अपने स्तर पर सभी लम्बित आवेदन पत्रों (जिसकी सूची सदन को प्रेषित की गयी है) का निस्तारण सुनिश्चित करें।

इस क्रम में श्री डी. के. गर्ग, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने उन्हे आश्वस्त किया कि इन सभी लम्बित आवेदनो की आद्यतन स्थिति से अतिशीघ्र अवगत कराया जायेगा।

बैठक के अंत में श्री **वाई. पी. बरार,, महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक** ने बैठक में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 23.08.2013 को आयोजित बैठक की कार्यबिन्दु

SN	Issue	Latest Position	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in all Districts of the State.**	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -18- Districts. During the Meeting itself it was informed by the State Govt. that in -47- Districts where formalities are in advanced stage, the allotment process may be completed by 1st week of September 2013.	Owing to the importance of the issue and also the Banks' commitment towards this Social cause, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in all the Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. It is all the more important because the Grant-in-aid of ₹1.00 crore admissible from Govt. of India is to be released to the Banks **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP)**
2.	**Formation of the Sub Committee of SLBC on RSETI under the convenership of General Manager Punjab National Bank**	In the SLBC Meeting dated 23.08.2013 the house expressed a need to form a Sub Committee of SLBC on RSETI to ensure grannular & through review of working of RSETIS in the State. It was proposed that this Sub Committee should be formed under the convenership of General Manager Punjab National Bank	PNB is required to form this Sub Committee by including various Lead Banks, NABARD along with State Project Coordinator, RSETI as member. Periodic Meetings should be held by the Sub Committee, progress to be reviewed regarding the construction of building and consolidated quarterly progress to be provided to SLBC for placing it in the SLBC Meetings along with the Agenda. **(Action : Punjab National Bank)**
3.	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level. 300 new B&M Branches were opened in a grand function organized at Lucknow on 29.03.2013, at the hands of Hon'ble Union Finance Minister & Hon'ble Chief Minister, UP. Banks are in the process of opening these branches in a phased manner. **As at June 2013 -440- Branches has been opened by the Banks (w.e.f 01.01.2013) and as at July 2013 total number of Branches opened is -765-**	The Banks are required to follow up the set deadline to achieve the set goals. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the monthly and quarterly progress is advised to the DIF, UP and SLBC on regular basis because it is one of the important Agenda points of the Monthly Meetings by the Chief Secretary, GoUP. **(Action : Banks & State Government)**
4.	**Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme in -6- identified Districts of State.**	-6- Districts of the State viz. Amethi & Raebareli (BOB), Etawah (CBI), Chitrakoot & Shrawasti (AB) and St. Kabir Nagar(SBI) have been identified for implementation of DBT Scheme w.e.f. 01.07.2013. Regular review is being done by Banks & SLBC and also at Govt. of India level. Various steps required to be implemented such as prompt issuance of Aadhaar number, seeding of Aadhaar number etc. are being attended to by concerned agencies with certain constraints which are overcome on regular basis.	Banks and the State Govt are required to implement the DBT Scheme in latter & spirit as success of the Scheme would pave way for its future coverage. **(Action : All Banks & State Govt)**
5.	**Recovery of Bank dues**	During the meeting it was informed that strict instructions for recovery of Bank dues under all RC filed accounts and also under SARFESAI Act 2002 have been reiterated by the State Government. Banks should attend the Recovery Meetings in Districts and also at the level of Board of Revenue at Lucknow. Still however, Banks raised some of the issue being faced by them at District level for recovery and requested for the State Govt. support. Addl. Director, Institutional Finance requested Banks for providing Districtwise list of problems being faced by them for its speedy redressal.	Banks should ensure reiteration of the instructions as received from DIF to its branches /offices. Banks should also ensure participation in the Recovery Meetings at District & State Level to discuss & review their chronic cases. As desired, Districtwise list of problems being faced by them, be provided to DIF with a copy to SLBC for its regular review through the forum of SLBC also. **(Action : All Banks & DIF, GoUP)**

ANNEXURE

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri P Srinivas	022- 66985888
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri D.K. Garg	0522-6677607
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Arun Pasricha	9415015471
4				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328
5				Asstt. Gen. Manager	Shri D.C. Soni	8004921329
6				Manager	Smt. Aparna Bhatt Dwivedi	7376343433
7				Assistant Advisor	Shri Gopal Prasad	9984811113
8	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief Gen. Manager	Shri K K Gupta	9453004901
9				Dy. General Manager	Shri Awadhesh Kumar	9506018285
10	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing Director	No	Dy. General Manager	Mrs Srabani Das	9972531772
11	State Bank of India. Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri A. K. Palit	8005488744
12		Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri V.S. Negi	8005493150
13				Chief Manager (RRB & Lead Bank)	Shri R. K. Srivastava	8005491073
14	Punjab National Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Field General Manager	Shri Y K Barar	
15				Asstt.General Manager	Shri M.C. Madan	8173000101
16	Allahabad Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Anurag Deep	9455049905
17				Senior Manager	Shri Ram Khelawan	9452258007
18	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri B.P. Dimri	9839034457
19				General Manager	Shri H K Behera	9918301580
20				Chief Manager	Shri Rajashri Baglari	9918702112
21				Senior Manager	Shri Moti Lal	9918702102
22	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager / State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S. K. Chaudhary	9936406606
23				Divisional Manager	Shri Amar Nath Mondal	9565678880
24	Syndicate Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Regional Manager	Shri P. S. Tuteja	9415550118
25				Senior Manager	Shri K. M Saxena	9415004955
26	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager/ Zonal Manager	Shri M. K. Gupta	9839013933
27				Senior Manager	Shri Lalsaram	9415520818
28	Central Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Ajay Vyas	9918002199
29	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri Vinay Verma	9793205559
30	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri P C Verma	9936873777
31	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri T.C Agarwal	9336631333

ANNEXURE

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
32				Senior Manager (Agri)	Shri KNVSB Gupta ji	8004530863
33	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Senior Manager	Shri Animesh Kulshrestha	9889321415
34	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager/ State Head	Shri. A. K. Bajpai	9839016070
35				Manager	Shri Jalendra Singh	9598059588
36	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	Yes	DGM/ Chief Regional Manager	Shri Ajay Kumar Raizada	9839010168
37				Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722
38	Oriental Bank of Commerce, Lko.	General Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri P S Hooda	9554966777
39				Asstt. General Manager	Shri Akhilesh Goyal	8853099002
40				Manager	Shri Bikram Bhuyan	9005977788
41	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	No	Dy. General Manager	Shri G. S. Narang	9839066415
42	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Anurag Rastogi	9415552782
43	State Bank of Hyderabad. New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Vipin Singh	9005161315
	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	No			
44	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri P. K. Roy	9695686699
45				Asstt. Manager	Ms Ajita	8756775522
46	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri B Radhakrishnan	7275008429
47	UCO Bank, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri R K Khanna	9794211841
48	United Bank of India, Lucknow	Chief Regional Manager	No	Chief Manager	Shri Ashok Kr. Singh	8960148034
49	Vijaya Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri A.K. Das	9935057850
50				Senior Manager	Shri S Murmu	9532110797
51	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S Gaur	9415113553
52	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri J V Purohit	7388899750
53				Chief Manager	Shri A K Verma	7388899783
54	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Nirmesh Kumar	8765956232
55	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700
56	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri. B. K. Pandit	9837036728
57	Purvanchal Bank	Chairman	No	General Manager	Shri S L Srivastava	9415210545
58	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shir D S Bainola	7895007722
59	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank	Chief General Manager	Yes	Chief General Manager	Shri Govind Kumar	7408407390
60	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri S C Dwivedi	8004400333
61	Axis Bank, Lucknow	Circle Head	No	Dy. Vice President	Shri Jeetandra Singh Rawat	7408811222

ANNEXURE

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
62				Asstt. Vice President	Shri Gautam Kher	9198085555
63	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	Vice President	Shri Anil Khugshal	9307510246
64				Sr. Manager	Shri Rajni Kant	9794830999
65	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Manager	Shri Rishi Saxena	9935163136
66				Regional Relationship Manager	Shri Misha Dua	8953990809
67				Chief Manager	Shri Surendera Dwivedi	8853989150
68	IDBI Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri K M Pradhan	9870008098
69	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	Yes	State Head	Shri Himanshu Mishra	9554888806
	ING Vysya Bank Ltd, Lucknow	Branch Head	No			
70	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Biju .K. Philip	9839222575
71	Kotak Mahindra Bank, Mumbai	State Head	No	Branch Manager	Shri Pushkin Mehrotra	9838078384
72	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri. Joy K.O.	7275488057
73	J&K Bank, Gurgaon	Asstt. Gen. Manager	No	Senior Executive	Shri Manzoor Ahmad	8009101174
74	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asso. Vice President	Shri S.C. Joshi	8009241100
75	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Manager	Shri Amit Kumar	9450767259
	Govt. of U.P.	Chief Secretary	No			
	Govt. of U.P.	Agriculture Production	No			
	Agriculture	Principal Secretary, GoUP	No			
	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No			
76	Institutional Finance	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri Majid Ali, IAS	0522- 2239768
	Industries & Export Promotion	Principal Secretary, GoUP	No			
	Dairy Development	Principal Secretary, GoUP	No			
	Khadi & Village Industry Board	Principal Secretary, GoUP	No			
	Social Welfare	Principal Secretary, GoUP	No			
77	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Project Director	Shri I. P. Kanaujia	9415022466
	MSME	Secretary, GoUP	No			
78	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Secretary	Shri L Venkateshwar lu	9415409983
79				Dy. Commissioner	Shri Chandra Shekher	9453415258
80				Officer	Shri Ram Narayan	9454405331
81	Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Dy. Director	Shri Sarveshwar Shukla	9415054007
82	Rural Development	Commissioner, GoUP	Yes	Commissioner	Shri K Ravindra Naik	9454464555
83				Mission Director, NRLM	Dr. Adarsh Singh, IAS	9454412671

ANNEXURE

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
84				Special Secretary	Shri Ashok Kumar	9454413811
85	State Urban Development Agency	Director	No	Project Director	Shri I. P. Kanojia	8573002205
86	U.P. Bhumi Sudhar Nigam Ltd.	Managing Director	No	Sr.Manager (Credit)	Shri Atul Kumar	9415086119
87	U.P. Minorities Fin. & Dev. Corp.	Managing Director	No	Officer incharge	Mohd. Waleem	0522-02286158
88	National Commission for SCs, GoI	Director	No	Asstt. Director	Shri Tarun Khanna	9455004893
89	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	No	General Manager	Shri P C Singh	9415002008
	U.P Backward classes Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	No			
90	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director	Yes	Director	Shri Shiv Singh Yadav	
91		Addl. Director	Yes	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102888
92				Asstt. Director	Dr Suman Srivastava	0522-4026354
93				Dy. Director	Shri G P Shukla	0522-4026354
94	Agriculture	Director	Yes	Director	Shri D M Singh	9235629301
95	Agriculture (Statistics)	Director	Yes	Director	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305
96				Jt. Director	Shri R K Gupta	9235629339
	National Horticulture Board	Director	No			
97	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	No	Asstt. Director	Shri V. P. Gupta	9415059359
98	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	9839959915
99	Saghan Mini Dairy Pariyojana	General Manager	Yes	General Manager	Dr. Mohan Swaroop	9450004476
100	Police Headquarter	Director General	No	Addll. S P (Crime)	Shri. Ramesh	9454401146
	Udyog Bandhu	Executive Director	No			
101	National Housing Bank	Regional Manager	No	Dy. Manager	Shri Saurabh Singh	9415511011
102	Ministry of Finance, GoI	Director (CP & MF)	Yes	Director (CP & MF)	Dr Alok Pande	
103	Ministry of MSME, GoI	Director	Yes	Director	Shri Sanjeev Chawala	9810908426
104	Ministry of Rural Development	State Project Co-ordinator	Yes	State Project Coordinator	Shri N. C. Sharma	9457837384
	LIC of India	Regional Manager	No			
	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No			
	United India Insurance Co. Ltd.	Nodal Officer	No			
	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No			
	New India Insurance Co.Ltd.	Regional Manager	No			
105	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rampal S Rawat	8935030301
	GOI	NIC				

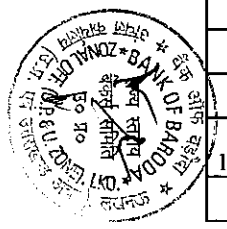

ANNEXURE

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
	Special Invitee					
106	Food & Civil Supplies	Food Commissioner	Yes	Food Commissioner	Smt Archana Agrawal	
107	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Jt. Director, Poultry	Dr. Ali Qidwai	8090396756
108				Addl. Director	Dr. P S Gautam	9919961071
109	Planning	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri Sanjiv Mittal	9935744444
110	Cooperatives	Principal Secretary, GoUP	No	Joint Secretary	Shri Waheed Ullah	9412422796
111	Panchayati Raj	Director	Yes	Director	Shri Saurabh Babu	9452212029
112				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singla	9839112344
113				Asstt.Gen. Manager	Shri K. R Kanojia	0522-6677722
114				Asstt.Gen. Manager	Shri B R Patel	9838193939
115				Sr. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721
116				Manager	Shri R K Agrawal	9415182483
117				Manager	Ms Silk Smita	0522-6677694
118				SWO	Ms Preeti Arya	0522-6677726
119				SWO	Ms Anjali Singh	0522-6677726